खट्टर की लफ्फाज नौटंकी के पूरे हुए चार साल

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब दस वर्ष तक चली कांग्रेस की हुड्डा सरकार से दुखी जनता संघ एवं भाजपा के अति अक्रामक प्रचारतंत्र के बहकावे में आ गयी और पहले केन्द्र में मोदी व फिर हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार को भारी बहुमत से सत्ता में ले आई। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कभी भाजपा का नाम तक नहीं जानते थे, जो छात्र एवं युवा संघ एवं भाजपा के चरित्र से परिचित नहीं थे, सभी झूठे एवं आक्रामक प्रचारतंत्र से इस कदर प्रभावित हो गये कि विधासनसभा चुनावों में 9-10 सीटों पर सिमटने वाली भाजपा को 56 सीटें दे दीं। लेकिन आज चार वर्ष बाद हरियाणा की जनता अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ पा रही है।

उधर बेशर्मी की इन्तहा देखिये, खट्टर जी अपने चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हुए तमाम प्रचार साधनों द्वारा जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। इस काम पर जनता के ही खून पसीने का सैकड़ों करोड़ फूंकने में उन्हें कतई कोई परहेज नहीं। सर्वमान्य सत्य है कि जो काम किये होते हैं वे खुद बोलते हैं और जनता को स्वत: दिखाई देते हैं। उनके लिए राजकोष का धन बर्बाद करके ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं होती।

खट्टर जी अपने कामों में बढ़-चढ़ कर गिनवाते हैं गीता जयंती समारोह जिस पर करीब 1700 करोड़ बहा दिये जो जनता के किसी काम नहीं आये। सैकड़ों करोड़ तथाकथित पौराणिक सरस्वती नदी की खुदाई पर लगा दिये। उसके बावजूद न तो कहीं वह नदी नजर आई न उसका पानी किसी ने पिया। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) सड़क बनाने का श्रेय लेने में भी उन्हें कतई कोई शर्म महसूस नहीं होती। विदित है कि यह सड़क बीते 15 वर्षों से बनती आ रही है। इसके निर्माण पर सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं लगना था और न लगा। हां, जिस-जिस कम्पनी को विभिन्न सरकारों ने इसके निर्माण का ठेका दिया था, सरकारों ने उन कम्पनियों को इस कदर निचोड़ा कि वे काम अधूरा छोड़ कर भाग गयीं। इस आधे-अधूरे काम को ही पूरा कराने में खट्टर को चार साल लग गये।

केएमपी का अब जो काम पूरा हुआ है वह भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं जी-टीवी चैनल के मालिक सुभाष चन्द्रा द्वारा किया गया है। मजे की बात तो यह है कि सड़क निर्माण के लिये राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी कतार में थे लेकिन उनकी दाल गली नहीं, दरअसल यह ठेका मोटी लूट कमाई का है। इसीलिये जब दो बार सुभाष चन्द्रा समय पर काम पूरा नहीं कर पाये तो कैबिनेट मीटिंग में उनका ठेका रद्द करवा कर कैप्टन अभिमन्यु ने छीनने का भरसक प्रयास किया था लेकिन सुभाष चन्द्रा की मजबूत जुगाड़बाज़ी के चलते उन पर कुछ जुर्माना लगा कर समयावधि बढा दी गयी। हाथ मलते रह गये कैप्टेन साहब गुस्से में मीटिंग छोड़ कर चले गये। इस प्रोजैक्ट पर सारा पैसा बैंको से लेकर कम्पनी लगाती है और उससे कई गुणा अधिक ब्याज व मुनाफ़ा उम्र भर कम्पनी कमाती रहेगी जो टोल के माध्यम से जनता से लूटा जायेगा।

लड़कियों के लिये हवा-हवाई कॉलेज

खट्टर पूरी बेशर्मी के साथ ढोल पीट रहे हैं कि लड़कियों के लिये उन्होंने 32 कॉलेज नये खोल दिये हैं और 27 अगले चरण में खोले जायेंगे। ऐसे तीन नकली कॉलेज इस ज़िले में भी खोले गये हैं। नचोली, मोहना व सेक्टर 2 बल्लबगढ में स्थित ये ऐसे कॉलेज हैं जिनकी न तो कोई इमारत है, न वहां कोई स्टाफ़ है न पढ़नेवाली छात्रायें हैं। जी हां, यही हकीकत है इन नकली एवं हवाई कॉलेजों की। इमारत के नाम पर आसपास के सरकारी स्कूलों के दो-चार कमरों पर कब्ज़ा करके कॉलेज का बोर्ड टांग दिया गया। स्टाफ़ के नाम पर आस-पास के सरकारी कॉलेजों के स्टाफ़ को पार्ट टाइम के तौर पर लगा दिया गया। विदित है कि किसी भी सरकारी कॉलेज में जरूरत का एक चौथाई स्टाफ़ भी नियमित नहीं है। उसमें से भी इसी स्टाफ़ को सप्ताह में 2-3 दिन के लिये इन हवाई कॉलेजों में पढाने जाना होता है। इसी तर्ज पर प्रिंसिपल भी लगभग आधे कॉलेजों में नियमित नहीं हैं

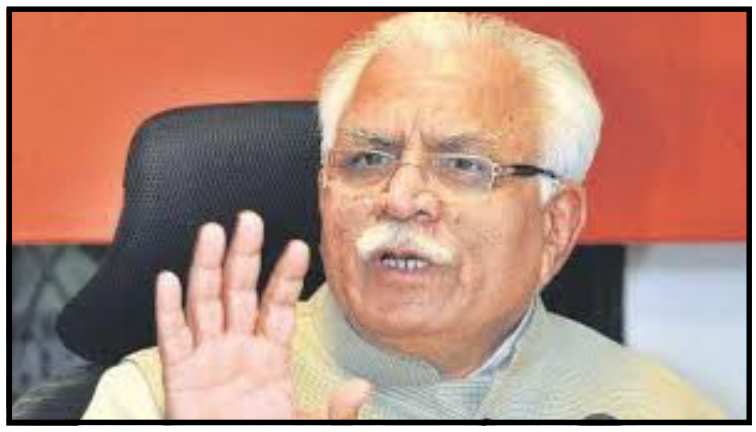

और जो हैं उन्हें भी एक से अधिक कॉलेजों का चार्ज दे रखा है।

इन हवाई कॉलेजों में पढ़ने वाले भी न के बराबर हैं। नचोली के कॉलेज में तो गणित की एक भी छात्रा नहीं है फ़िर भी नेहरू कॉलेज से एक प्रोफ़ेसर वहां पढाने जाता है। यानी वहां कोई पढने वाला नहीं और जहां पढ़ने वाले हैं वहां कोई पढाने वाला नहीं। इन हवाई कॉलेजों में तो कोई दाखिला लेने वाली भी नहीं थी। प्रिंसिपलों व स्टाफ़ पर दबाव डाल कर वहां नाम मात्र को छात्रायें दाखिल की गयी। हां उन शहरी छात्राओं का दांव जरूर लग गया जिनका मैरिट के आधार पर दाखिला नहीं हो पा रहा था, उन्होंने जरूर इनमें दाखिला ले लिया क्योंकि उनको पता है कि देर सबेर में हवाई कॉलेज भी पुराने कॉलेजों में समाहित हो जायेंगे। इन नकली कॉलेजों में परीक्षा केन्द्र भी नहीं बन पायेंगे इसलिये परीक्षा देने के लिये भी छात्रों को पुराने कॉलेजों में ही जाना पड़ेगा।

स्कूलों की दुर्दशा

स्कूलों का हाल तो और भी बुरा है। अधिकांश सरकारी स्कूलों का परिणाम ज़ीरो से दस प्रतिशत तक ही सिमट जाता है यानी कि 100 छात्रों में से 10 ही पास हो पाते हैं। हर साल यही होता है और हर साल इस गिरते परिणाम की जांच का नाटक किया जाता है। नाटक करने की वैसे तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि जांच तो हुई पड़ी है। जब स्कूलों में 30 000 शिक्षकों की कमी है तो बच्चे पढेंगे कहां से? इतना ही नहीं जो शिक्षक हैं भी वे बच्चों को पढाने के अलावा बाकी सब काम करते हैं। चुनाव सम्बन्धी काम तो आजकल सारा साल चलता रहता है। कभी कोई चुनाव तो कभी कोई। कभी वोटर लिस्टें बन रही हैं या नये वोटर बन रहे हैं, पुराने कट रहे हैं, बूथ लेवल की समस्यायें आदि के सारे काम इन्हीं शिक्षकों को ज़िम्मे हैं। जनगणना होगी तो शिक्षक करेंगे। पोलियो अथवा अन्य कोई राष्ट्रीय अभियान होगा तो शिक्षक करेंगे। नेताओं की चाकरी करेंगे तो शिक्षक करेंगे। ऐसे में बच्चे कहां से पढेंगे? और परिणाम ज़ीरो प्रतिशत नहीं आयेगा तो क्या आयेगा?

हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का खोखला दावा

खट्टर से बीते 4 साल में ले-दे कर मात्र करनाल वाला एक मेडिकल कॉलेज ही चालू हो पाया जो बीते 7 वर्षों से कल्पना चावला के नाम से बनाया जा रहा था। घोषणावीर खट्टर की घोषणाओं में कोई कमी नहीं। इसी क्रम में उन्होंने मधुबन पुलिस एकेडमी के सामने एक मेडिकल युनिवर्सिटी स्थापित करने की भी घोषणा की थी। उसके लिये सैंकड़ों एकड़ ज़मीन अधिग्रहीत करने की बात भी कही थी। लेकिन टॉय-टॉय फ़िस। नई मेडिकल युनिवर्सिटी तो क्या खोलते खट्टर जी पुरानी युनिवर्सिटी ही वेंटीलेटर पर पड़ी है। जी हां, रोहतक मेडिकल कॉलेज को युनिवर्सिटी का दर्जा देकर राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों को उससे जोड़ दिया गया। लेकिन इसे चलाने का खर्चा सरकार के पास नहीं है। इसलिये नाम मात्र के स्टाफ़, वह भी पुराने सेवानिवृत कर्मचारियों से औने-पौने वेतन पर, काम चलाया जा रहा है। खर्चे के लिये धन उगाही के लिये राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों पर अनाप-शनाप जुर्माने किये जा रहे हैं। आर्थिक संसाधन बढाने के लिये जुर्माने लगाने से घटिया कोई बात हो नहीं सकती। इसके बावजूद तमाम कॉलेजों के संचालक एवं छात्र परेशान रहते हैं क्योंकि स्टाफ़ की कमी के चलते उनके कोई भी काम समय पर हो नहीं पाते, उन्हें बार-बार युनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तो गई ऐसी-तैसी में पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज (रोहतक, खानपुर, नूह व अर्ध सरकारी अग्रोहा) को चलाने के लिये भी पर्याप्त बजट नहीं है। रोहतक मेडिकल कॉलेज सुचारु ढंग से चलाने के लिये कम से कम 4000 करोड़ सालाना चाहिये जबकि इसे मिलता है मात्र 700 करोड़। ऐसे में न तो वहां पर्याप्त स्टाफ़ है न सफ़ाई आदि की व्यवस्था। दवाओं की तो बात छोड़िये रूई व पट्टी तक भी मरीज़ों से मंगवाई जाती है। स्टाफ़ की कमी के चलते एक ओर तो अस्पताल सड़ रहा है दूसरी ओर मरीज़ों की बढ़ती भीड़ को संभाल पाना असंभव हो रहा है। इसी अव्यवस्था के चलते कुछ मरीज़ तो सीधे दिल्ली की ओर निकल लेते हैं तो कुछों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल वहां के एम्स व सफ़दरजंग को रैफ़र कर देता है। विदित है कि दिल्ली के एम्स व रोहतक मेडिकल कॉलेज की स्थापना लगभग एक साथ ही हुई थी। यदि राज्य सरकारों ने इसे पर्याप्त बजट देने के साथ-साथ राजनीति का अखाड़ा न बनाया होता तो रोहतक से दिल्ली की ओर मरीज़ न आते।

खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज व नूह मेडिकल कॉलेज के लिये हरियाणा सरकार अभी तक न तो पर्याप्त उपकरण खरीद पाई है और न ही पर्याप्त फ़ेकल्टी एवं अन्य आवश्यक स्टाफ़ की ही भर्ती कर पाई है। इसलिये एमसीआई को धोखा देने के लिये निरीक्षण के समय सरकार अपने अन्य अस्पतालों से अस्थाई तौर पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर देती है। विदित है कि राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में आवश्यकता के आधे भी डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, नर्सिंग व अन्य स्टाफ़ का भी यही हाल है।

हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करने वाले खट्टर की यह हकीकत यहीं समाप्त नहीं हो जाती। राज्य भर के किसी भी अस्पताल में आवश्यक दवाओं का सदैव अभाव बना रहता है। और तो और कुत्ता काटे (रेबिज़) के टीके तो मुश्किल से ही कभी कभार खट्टर के अस्पतालों में मिल पाते हैं। इसके लिये बजट की कमी का रोना तो रोया ही जाता है लेकिन जो बजट खर्च भी होता है उसका 20 से 30 प्रतिशत रिश्वतखोरी एवं बर्बादी की भेंट चढ जाता है।

सरकारी अस्पतालों में तो खट्टर सरकार बजट का रोना रोती है लेकिन ईएसआईसी के जो अस्पताल सरकार के जिम्मे हैं उन्हें सही ढंग से चलाने में सरकार को क्या मौत पड़ रही है? विदित है कि ईएसआईसी के अस्पतालों व डिस्पेंसरियों को चलाने के लिये तमाम तरह के स्टाफ़ की भर्ती, तमाम तरह के उपकरणों व दवाओं आदि की खरीद का जिम्मा राज्य सरकार के पास है। जबकि इसके खर्च का मात्र 8 वां भाग ही राज्य सरकार को लगाना होता है। यानी 800 करोड़ के खर्च में से 700 करोड़ ईएसआईसी वहन करती और राज्य सरकार मात्र 100 करोड़। लेकिन सरकारी निकम्मेपन व जनविरोधी नीतियों के चलते राज्य सरकार बजट ही मात्र 120-140 करोड़ का बनाती है। इसे सरकार की मूर्खता कहें या राज्य की सवा करोड़ जनता, जो ईएसआईसी में कवर्ड है, से दुश्मनी कहें?

जीरो भ्रष्टाचार का खोखला दावा

घोषणावीर मोदी की तर्ज़ पर खट्टर ने भी घोषणा की थी कि वे भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक बात है, घोषणा करने में जाता ही क्या है, कुछ भी कितना भी घोषित कर दो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वास्तविकता जनता के सामने है। सरकार के किसी भी विभाग के किसी भी दफ़्तर में भ्रष्टाचार घटना तो दूर बढता ही चला गया। खट्टर साहब फ़र्माते हैं कि उनका तो न कोई घर है न परिवार वे किसके लिये रिश्वतखोरी करेंगे। ठीक है खट्टर साहब रिश्वतखोरी नहीं करते होंगे, मान लिया, परंतु इससे आम जनता को तो कोई लाभ नहीं। जनता को लूटने वाले थाने, तहसील, 'हूडा', नगर निगम, सेल टैक्स आदि कोई भी तो महकमा ऐसा नहीं जहां जन साधारण को लूटा न जाता हो। भ्रष्टाचार से मुक्त करने के नाम पर खट्टर सरकार ने करीब 3 वर्ष पूर्व 'हूडा' विभाग के तमाम कर्मचारियों का फ़रीदाबाद व गुड़गांव से तबादला कर दिया था। लेकिन मजे की बात है कोई एक माह बाद तो कोई दो माह बाद वापस अपने-अपने ठिकानों पर आ जमे। कोई-कोई तो एक दिन के लिये भी यहां से नहीं हटे। हां तैनाती पुराने स्थानों पर बहाल कराने के लिये उन्होंने जो रिश्वतें जहां-तहां दी उनकी वसूली जनता से जरूर अतिरिक्त रूप से कर ली।

नगर निगम पहले यमुना एक्शन प्लान के तहत सैंकड़ों करोड़ रुपये पचा गया तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के नाम पर हज़ारों करोड़ डकार गया और अब उसके हाथ 'स्मार्ट सिटी' का खजाना लग गया। काम इन तीनों योजनाओं में सीवर पेयजल व सड़कों आदि का ही मुख्य तौर पर होता है। लेकिन वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं होता। सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुये दावा करती है कि उसने फ़लां काम पर इतने करोड़ तो फ़लां काम पर इतने अरब रूपये खर्च कर दिये। ग्रामीण विकास के नाम पर इतने अरब रुपये ग्राम पंचायतों को दे दिये। परन्तु जनता के खून पसीने की कमाई का यह अरबों-खरबों जा कौन से गटर में रहा है, यह खट्टर जी को नज़र नहीं आ रहा। यदि यह सारा पैसा वास्तव में ही धरातल पर खर्च हो जाय तो किसी भी सेवा का अभाव न रहे।

हर जगह धोखा ही धोखा!

किसानों के वोट ठगने के लिये भाजपा ने स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू करने व उनकी आय दोगुणी करने का झांसा दिया था। यह सब तो दूर रहा किसानों को उनकी उपज का सरकारी समर्थन मूल्य तक कभी नहीं मिला। चुनाव निकट देख समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा तो कर दी लेकिन वास्तव में पुराना समर्थन मूल्य ही नहीं मिल रहा। आजकल बाजरे की खरीद में खट्टर सरकार ने इतने अड़ंगे लगा दिये हैं कि किसान को अपना बाजरा आधे दामों बेचना पड़ रहा है।

इसी तरह फ़सल बीमा योजना के नाम पर किसानों से जबरी वसूली एवं सरकारी खाते से बीमा कम्पनियों को तो मोटा मुनाफ़ा कमवा दिया लेकिन किसान को तनिक भी लाभ नहीं हुआ।

यह खट्टर सरकार का ही 'कमाल' था जो गत दो वर्षों से गुड़गांव जैसे अति आधुनिक शहर के बीच राजमार्ग पर सैंकड़ों वाहन रात भर केवल इसलिये खड़े रहे कि बरसाती पानी से सड़क डूब गयी थी। विदित है कि इससे पहले बरसाती पानी स्वत: बह कर निकल जाता था, लेकिन खट्टर के राज में पानी निकासी के चैनलों पर कब्ज़े करा दिये गये जो अभी तक भी कायम हैं।

कर्मचारियों को नीतियों में दखल का अधिकार नहीं- यानी खट्टर सरकार तबाही मचाये तो उसे रोका न जाये

फ़रीदाबाद (म.मो.) रोडवेज हड़ताल के संदर्भ में मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने एक प्रवचन में फ़र्माया है कि कर्मचारी अपनी सीमा में रह कर नौकरी करें। उन्हें सरकार की नीतियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नीति निर्धारण का अधिकार केवल सरकार का है। उनका यह प्रवचन परिवहन विभाग यानी रोडवेज बसों का कारोबार बंद करके सारा धंधा निजी कम्पनियों को बेचने से सम्बन्धित था।

सुधी पाठक बखूबी समझते हैं कि रोडवेज जैसे मोटी व नकद कमाई वाले इस विभाग का सरकार ने कैसे बेड़ा गर्क किया है। 4000 से अधिक बसों के इस बेड़े से करोड़ों की रोज़ाना कमाई की जगह निकम्मी सरकार के भ्रष्ट प्रशासन ने घाटे का कारोबार बना कर रख छोड़ा। नई-नई बसें तो खरीदी जाती हैं क्योंकि खरीद पर कमीशन मिलता है, परन्तु इनको चलाने वाले ड्राइवर-कंडक्टर व अन्य आवश्यक स्टाफ़ की कमी से ये बसें बेकार खड़ी रहती हैं। नियमित एवं ज़िम्मेवार ड्राइवर-कंडक्टर की जगह दिहाड़ीदार ड्राइवर-कंडक्टर इस तरह भर्ती किये जाते हैं जैसे ईंट-गारा ढोने वाले दिहाड़ीदार मज़दूरों को चौक से पकड़ कर लाया जाता है। ऐसे स्टाफ़ को 50 लाख की बस सौंप देना जिसकी कोई जवाबदेही न हो कैसे कुछ कमा कर दे सकता है।

वर्कशॉप स्टाफ़ व असली स्पेयर पार्ट्स के अभाव में बसों की मुरम्मत तब तक नहीं कराई जाती जब तक वह बिगड़ कर, भरी सवारियों सहित सड़क पर न खड़ी हो जाये। छोटे-छोटे नुक्स जो अच्छे मिस्त्री द्वारा केवल दो नट कसने या चार हथौड़े मारने भर से ठीक हो सकते हैं, उनकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। इसके परिणामस्वरूप आये दिन बसें सड़कों पर बिगड़ी खड़ी रहती हैं और सवारियां कोसती हैं ड्राइवर को जिसका कोई कसूर नहीं होता।

रोडवेज के तमाम कर्मचारी संगठन बरसों से सरकार की इन्हीं निकम्मी नीतियों का विरोध करते आये हैं। दरअसल सरकार की यह निकम्मी नीति इस सरकारी व्यवसाय को इस कदर बदनाम करने की रही है कि लोग विकल्प के तौर पर निजी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को चाहने लगें। इसके विपरीत कर्मचारी चाहते रहे हैं कि यह व्यवसाय सरकार के हाथ में रहे और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार व निकम्मापन समाप्त करके सरकारी खजाने में अच्छा-खासा मुनाफ़ा जाये।

यही वह सैद्धांतिक मतभेद है जो सरकार व कर्मचारी संगठनों के बीच खड़ा है। कर्मचारी जो देश के नागरिक भी हैं तो वे कैसे न सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करें। उनका पूरा अधिकार ही नहीं कर्त्तव्य भी है सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में डट कर संघर्ष करने का। इस बीच तमाम सरकारी ज़ोर-आजमायश के बावजूद रोडवेज़ हड़ताल ज़ारी है और इनके समर्थन में उतरे तमाम अन्य कर्मचारी संगठनों ने इनके संघर्ष को और अधिक शक्ति प्रदान की है। दूसरी ओर इस हड़ताल से परेशान यात्री भी अब बखूबी समझने लगे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ही इन्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है।